Review of Research Journal
Vol.1,Issue.V/Feb; 12pp.1-4 **डी एन यादव** **ISSN:- 2249-894X**

ORIGINAL ARTICLE

वैश्वीकरण/भूमंडलीकरण की चुनौतियाँ और गाँधीवाद

डी एन यादव
सह – आचार्य, राजनीतिक विज्ञान विभाग , पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया.

सारांश :

वैश्वीकरण/भूमंडलीकरण का अपना अर्थ है और इसका उद्देश्य उच्चतम विकास की दर, आत्मनिर्भरता, संपूर्ण रोजगार और बेहतर जीवन स्तर को प्राप्त करना है। यह माना जाता है कि यह समानता के साथ विकास करे और इन विकासशील राष्ट्रों में रह रही अधिकतर जनसंख्या की स्थिति में सुधार का प्रयत्न करें। अभाग्यवश, औद्योगिक रूप से समुन्नत इन देशों में भूमंडलीकरण से सीमित जनसंख्या या जनसंख्या के एक चुने हुए निश्चित भाग को ही सहायता प्राप्त होती है। कुछ दशकों पहले गाँधीजी के विषय में सोचा जा रहा था कि जैसे–जैसे भूमंडलीकरण बढ़ेगा, जीवन का तकनीकीकरण, उपभोक्तावाद बढ़ेगा और गाँधीजी की याद धुंधली हो जाएगी, किन्तु हर गुजरते दिन के साथ गाँधीजी की मौजूदगी बढ़ती ही जा रही है। पहले गाँधीजी भारत तक थे, अब गाँधीजी दुनिया में फैले हैं।

भूमिका

वैश्वीकरण/भूमंडलीकरण के दौर में गाँधीजी सार्वभौमिक हो गए हैं। यह अकारण नहीं है कि ओबामा से लेकर एंजेला मार्केल और कोफी अन्नान से लेकर डेविड कैमरूल तक अपने भाषण में गाँधीजी को याद करते हैं। ओबामा ने शपथ लेते समय सबसे अधिक बार गाँधीजी को याद किया। जिस गाँधीजी को कभी कांग्रेस ने जीते जी भुला देने की, अनदेखी करने की कोशिश की थी। आज वही गाँधीजी दुनिया को झकझोर रहे हैं। दरअसल पूँजीवाद के संकट ने गाँधीजी को ज्यादा प्रासंगिक बना दिया है। पूँजीवाद के मौजूदा संकट से स्पष्ट हो गया है कि यह महज पूँजी का संकट नहीं है, बल्कि यह विचारधाराओं का भी संकट है, आज दुनिया में कोई ऐसी बड़ी विचारधारा नहीं बची, जिससे लोगों को सहारा मिले। समाजवाद के पतन और पूँजीवाद के संकट से भविष्य को लेकर असुरक्षा पैदा हो गई है। जब बड़ी विचारधाराएँ मौजूद होती हैं तो लोगों में समर्पण, त्याग, आत्मोत्सर्ग की भावना रहती है, लेकिन जब विचारधाराएँ समाज के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए पतन का कारण बन जाती हैं तो इससे वैयक्तिक और सामूहिक दोनों तरह के विश्वास हिल जाते हैं।

पूँजीवाद के साथ यही हुआ है और समाजवाद को पहले से ही पूँजीवाद ने रास्ते से बाहर कर दिया था। गाँधीजी के अगर समूचे व्यक्तित्व को देखें, तो वह बेहद प्रासंगिक है। अगर उन्हें पढ़ने का जोखिम उठाएँ तो लगेगा कि वह तकनीकी कारण, मशीनीकरण और आधुनिक किस्म के जनतंत्र के विरोधी हैं, लेकिन जब गहरे उतरकर देखते हैं, तब पता चलता है कि उनका विरोध इससे नहीं, बल्कि समाज को किनारे करने से है। वह तकनीकी के जरिये समाज में पैदा होने वाले विचलन के विरोधी हैं। गाँधीजी बड़े पैमाने पर पूँजी के भी विरोधी हैं। उनकी नजर में बड़ी पूँजी अपने आपको और बड़ा बनाने की फिराक में रहती है और उससे पूँजी के बहाव का एक वेहद अनियंत्रित क्रम शुरू हो जाता है। हकीकत में ऐसा ही होता है। बड़ी पूँजी और मशीनीकरण के विरोध के पीछे भावना है कि समाज ज्यादा समरस, ज्यादा एकजुट और ज्यादा आत्मनिर्भर बने। जब तक समाजवाद नई चमक बिखेर रहा था और पूँजीवाद नई ऊँचाइयाँ

हासिल कर रहा था, तब तक गाँधीजी के विचार अप्रासंगिक लग रहे थे, लेकिन अब जब समाजवाद मौजूद नहीं है और पूँजीवाद संकट में फँसा है तो गाँधीजी की एक सदी पहले की प्रगतिहीन बातें बेहद मानवीय, बेहद सामाजिक और बेहद भविष्यकालिक लगने लगी हैं। आज भले बहुत खुलकर यह बात सामने न आ रही हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि यूरोप और अमेरिका में जो मंदी गहरी होती जा रही है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वह है पूँजी का संकेन्द्रण।

ब्रिटेन में गरीब और अमीर के बीच का फासला बहुत अधिक है। भारत में भी भविष्य में यही होने के आसार बन रहे हैं। भले अमेरिका के पास दुनिया को छह बार पूरी तरह से तहस–नहस कर डालने के हथियार हों, लेकिन हकीकत यह है कि आज 1 करोड़ 80 लाख लोग पूरी तरह गरीब हैं। एक करोड़ 90 लाख या तो बेरोजगार हैं या आंशिक बेरोजगार हैं। आधुनिक तकनीकी समीकरण पर आधारित लोकतंत्र के भी गाँधीजी विरोधी हैं और तमाम मामलों में मौजूदा दुनिया की सफलताएँ गाँधीजी के पक्ष में खड़ी होती हैं।

आज के राजनेताओं और युवाओं ने गाँधीजी के विचारों को भूला दिया है। गाँधीजी का आर्थिक दर्शन आज प्रासंगिक नजर आ रहा है। गाँधीजी के आर्थिक आर्थिक दर्शन में सबसे निचले व्यक्ति को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। उन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा पेश की। वह लघु उद्योगों को स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उनके जाने के बाद किसी भी सरकार ने इस विचारों पर ध्यान नहीं दिया।

गाँधीजी को इस बात का इल्म 1930 के आसपास ही होने लगा था। उन्होंने इसका जिक्र इंडिया माई ड्रीम में किया है। इसके मूल में जो कारण नजर आता है, वह है क्रांतिकारी मूवमेंट से जुड़े शिक्षित लोगों का विदेशी मानसिकता से ओतप्रोत होना। ऐसे लोगों ने विकास का पश्चिमी मॉडल अपनाने की कोशिश की। इसकी चरम सीमा 1991 के बाद तब दिखाई देने लगी जब देश में उदारीकरण की नीतियों को लागू किया गया। उदारीकरण के बाद सामाजिक निष्ठा की सैद्धांतिक बात को भी भुला दिया और कहा गया कि आने वाले 20 साल में देश का भरपूर विकास हो जाएगा, लेकिन आज 15 साल बीत जाने के बाद भी देश के निचले तबके की हालत में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। आज जिस विकास की बात की जा रही है, वह सिर्फ 3 प्रतिशत लोगों में ही दिखाई देती है, जबकि 97 प्रतिशत आबादी आज भी बेहाल है।

गाँधीजी ने स्वदेशी और ग्रामीण रोजगार की जो बातें कहीं, उन्हें आज भुला दिया गया है। आज का युवा वर्ग वेस्टर्न मॉडल को अपनाने के लिए उतावला है, वह सब कुछ भुलाकर अच्छी जींस और परफ्यूम आदि पाना चाहता है। उसने वर्ग सहयोग की धारणा को दरकिनार कर दिया है। वह हर तरफ से उपभोक्तावाद की ओर बाहे फैलाए खड़ा है। इस काम में उसका सहयोग हमारे फिल्मी हीरो, क्रिकेटर आदि कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर सचिन तेन्दुलकर तक सभी अपने स्वार्थों की बजह से उन चीजों का प्रचार कर रहे हैं, जिनकी आम आदमी को कोई जरूरत नहीं है। ये चीजें लोगों की सेहत को भी नुकसान पहुँचाती हैं।

गाँधी जी के विचारों को आज के हालात में देखें तो गाँधीजी धीरे–धीरे हमसे दूर निकल रहे हैं। हम औद्योगीकरण की नीतियों को अपना रहे हैं। हमारा शासक–वर्ग विकास के पश्चिमी मॉडल को ही सही मानता है। पश्चिम की नई से नई तकनीक को अपने देश में अपनाने की कोशिश की जाती है, बिना ये जाने की उसकी हमारे देश में जरूरत है या नहीं। भोग और विलासिता के उत्पादों की पुरजोर मांग हो रही है। ऐसे हालत को देखते हुए तो नहीं लग रहा है कि आने वाले 15–20 सालों में गाँधीजी के विचारों को कोई सार्थक परिणति में पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। गाँधी–जयंती की रस्म को निभाने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन उनके विचारों पर बात करने की कोशिश नहीं हो रही। आज से 20–25 साल बाद जब नई आर्थिक नीतियों के बुरे नतीजे समाज को तोड़ देंगे, तब गाँधीजी के विचारों की प्रासंगिकता महसूस होगी। ऐसा समय भविष्य के गर्भ में है।

स्वतंत्रता–प्राप्ति के तुरंत बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को चुना, जिसके अंतर्गत सरकार ने विकास का मार्ग अपनाया। इसने कई बड़े उद्योग स्थापित किए और धीरे–धीरे निजी क्षेत्र को विकसित होने दिया।

बरसों तक भारत ने अन्य देशों से ऋण लिया। कुछ स्थितियों में सरकार ने लोगों के पैसे को भी मुक्त हस्त से खर्च किया। 1991 में भारत ऐसी स्थिति में पहुँच गया, जिससे वह बाहर के अन्य देशों के ऋण लेने की विश्वसनीयता खो बैठा। कई अन्य समस्याओं जैसे बढ़ती कीमतें, पर्याप्त पूँजी की कमी, धीमा विकास और प्रौद्योगिकी के पिछड़ेपन ने संकट को बढ़ा दिया। सरकारी खर्च आय से कहीं अधिक हो गया। इससे भारत को भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को तेज करने तथा दो अंतराष्ट्रीय संस्थाओं, विश्व बैंक और अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोश के सुझाव के अनुसार अपने बाजार खोलने को विवश किया।

सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति को नई आर्थिक नीति कहा जाता है। इस नीति के अंतर्गत कई गतिविधियों को, जो सरकारी क्षेत्र द्वारा ही की जाती है। इस नीति के तहत कई गतिविधियों को, जो सरकारी क्षेत्र में ही की जाती थीं, निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया। निजी क्षेत्र को कई प्रतिबंध से भी मुक्त कर दिया। उन्हें उद्योग प्रारंभ करने तथा व्यापारिक गतिविधियाँ चलाने के लिए कई प्रकार की रियायतें भी दी गई।

देश के बाहर से उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को उत्पादन करने तथा अपना माल और सेवाएँ भारत में बेचने के लिए आमंत्रित किया गया। कई विदेशी वस्तुओं, जिन्हें भारत में पहले बेचने की अनुमति नहीं थी, अब अनुमति दी जा रही है।

भारत में भूमंडलीकरण के अंतर्गत विगत एक दशक में कई विदेशी कंपनियों द्वारा मोटर–गाड़ियों, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंसकरण उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन इकाइयाँ लगाई गई हैं। इससे भी बढ़कर कई उपभोक्ता वस्तुओं विशेतः इलेक्ट्रानिक्स उद्योग में जैसे रेडियो, टेलीविजन और अन्य घरेलू उपकरणों की कीमतें घटी हैं। दूरसंचार–क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। अतीत में जहाँ हम टेलीविजन पर एक या दो चैनल देख पाते थे, उसके स्थान पर अब हम अनेक चैनल देख सकते हैं। हमारे यहाँ सैक्यूलर फोन प्रयोग करने वालों की संख्या करोड़ों में हो गई है, कम्प्यूटर और अन्य आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग खूब बढ़ा है। जब विकासशील देशों को व्यापार के लिए विकसित देशों से सौदेबाजी करनी होती है तो भारत एक नेता के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक क्षेत्र, जिसमें भूमंडलीकरण भारत के लिए उपयोगी नहीं है। वह है रोजगार पैदा करना। यद्यपि इसने कुछ अत्यधिक कुशल कारीगरों को अधिक कमाई के अवसर प्रदान किए, परंतु भूमंडलीकरण व्यापक स्तर पर रोजगार पैदा करने में असफल रहा। अभी कृषि जो भारत की रीढ़ की हड्डी है, भूमंडलीकरण का लाभ मिलना शेष है। भारत के अनेक भू–भागों को विश्व के अन्य भागों में उपलब्ध भिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी की कुशलता से प्रयोग कर सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। विकसित देशों में खेती के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों को अपनाने के लिए भारतीय उपकरणों की आवश्यकता है। भूमंडलीकरण द्वारा अभी भारत के लाखों घरों में सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करानी है।

भारत में भूमंडलीकरण नब्बे के दशक में, भारत को बाह्योन्मुखी बनाने के साथ शुरू हुआ। 1991 में भारत में नयी औद्योगिक नीति को स्वीकार किया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर सुधार हुआ।

नयी औद्योगिकी नीति को अपनाने के पूर्व भारत का भुगतान संतुलन चालू खाते में अत्यंत ऋणात्मक था, मुद्रास्फीति बहुत अधिक थी, गरीबी उच्च स्तर पर था, तथा केन्द्र और राज्य सरकारें राजकोषीय घाटे के जाल तेजी से आगे बढ़ रहा है। भूमंडलीकरण के इस दौर में भारत एक ऋणदाता राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है।

भूमंडलीकरण से भारत में विदेशी पूँजी का आगमन हो रहा है, आधारभूत संरचनाओं का विकास हो रहा है, रोजगार में वृद्धि हो रही है। आधुनिक तकनीकों तथा तकनीकी विशेषनों में वृद्धि हो रही है, जिससे हम अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर पा रहे हैं, तीव्र औद्योगिकीकरण हो रहा है, जिससे प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो रही है और उपभोक्ताओं को वस्तुएँ उचित मूल्यों में प्राप्त हो रही है। इंटरनेट और कम्प्यूटर के माध्यम से सभी विषयों में जानकारी प्राप्त हो रही है, शैक्षणिक कार्यक्रमों का सेटेलाइट के माध्यम से प्रसारण हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में उन्नत बीजों तथा तकनीकों का प्रयोग किए जाने से उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

परंतु इन उपलब्धियों के साथ–साथ भूमंडलीकरण प्रभाव भी पड़ रहा है। हमारे लाभांश का विदेशों में हस्तांतरण हो रहा है। लघु एवं कुटीर उद्योग का मार्ग अवरूद्ध हो रहा है, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ रहा है। विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय कम्पनियों का अधिग्रहण किया जा रहा है। विदेशी वस्तुओं का प्रयोग बढ़ रहा है। इलेक्ट्रानिक बाजारों में चीन में बनी चाइना वस्तुओं का एकाधिकार सा हो रहा है। भारतीय किसान ट्रांसजैनिक कृषि के जाल में फँसकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। भारत में पाई जाने वाली नीम, हल्दी आदि का, जिसका जड़ से लेकर फूल पत्तियाँ सभी उच्च औषधि मूल्य वाली होती हैं, इनको भी विदेशियों ने पेटेंट करा लिया है।

भूमंडलीकरण के नकारात्मक प्रभावों को गाँधीवादी विचारधारा से कम किया जा सकता है। गाँधीवादी विचारधारा स्वदेशी वस्तुओं का अधिक उपयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल देता है। वह तीव्र औद्योगीकरण का विरोध करता है, तथा लघु उद्योगों के विकास पर जोर देता है। यदि हम गाँधीवादी विचारधारा के अनुसार विदेशी वस्तुओं के उपयोग से बचते हुए अपने देश में बनी वस्तुओं का अधिक प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से भूमंडलीकरण के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं।

वैश्वीकरण व पूँजीवादी व्यवस्था में जिन व्यक्तियों ने प्रगति की, वह धनी व्यक्ति बने, परंतु पूँजीवादी व्यक्ति बनने के लिए व्यक्ति ने मजदूरों का शोषण किया। अपनी लालसा को सदैव बनाये रखा कुछ और पाने की जिज्ञासा में व्यक्ति धनी तो होता चला गया, परंतु अपनी नैतिकता को खोता भी चला गया। एक राजा चाहे जितने राज्यों पर विजय प्राप्त कर ले, परंतु उसकी असंपृक्तता बढ़ती ही जाती है, पूँजीपति व्यक्ति का धन, शौर्य बढ़ता चला है, उसकी संपत्ति को उसके बाद उसके उत्तराधिकारी प्राप्त कर लेते हैं, परंतु अपने कर्मों का फल नहीं भोगता है।

विकासशील और अविकसित राष्ट्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास अल्प है। इस कारण यह विकसित राष्ट्रों के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कमजोर राष्ट्रों को सूचना तकनीक के क्षेत्र में सहायता मिलती है, परंतु दूसरी तरफ नई उपनिवेशवादी व्यवस्था ने आर्थिक गुलामी के द्वारा रास्ते खोल दिये हैं। जब किसी भी राष्ट्रों का वर्चस्व हो तब उस राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव समूह का बल बना रहता है। विश्व–अर्थव्यवस्था में उदारीकरण निजीकरण और भूमंडलीकरण का प्रभाव वैश्विक राजनीति पर प्रदर्शित हो रहा है। जिस कारण अनेक राष्ट्र स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान में विश्व भूमंडलीकरण का प्रभाव प्रत्येक राष्ट्र पर है। अब राज्य उपनिवेशवाद का स्थान बहुराष्ट्रीय उपनिवेशवाद ने ले लिया है। भविष्य की इस समस्या की कल्पना गाँधीजी ने आजादी पूर्व ही कर दिया था। वर्तमान के बहुराष्ट्रीय उपनिवेशवाद और कंपनियों के विस्तार को बढ़ावा देने वाले विश्व–बैंक, अंतराष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व–व्यापार संगठन का नापाक शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने बुनियादी नींव आंतरिक संसाधनों पर निर्भरता के निर्णयों को खोते जा रहे हैं। यह सभी कारण अवनति को उत्पन्न करते हैं। इस दृश्य की कल्पना गाँधीजी ने वर्षों पूर्व ही कर दिया था। इसलिए गाँधीजी के विचारों की प्रासंगिकता वैश्वीकरण के दौर में बढ़ जाती है।

संदर्भ :

1. भूमंडलीकरण विचार नीतियाँ और विकल्प–कमल नयन काबरा प्रकाशन संस्थान, दिल्ली, 2005, पृ0–32
2. गाँधी–दर्शन विश्व–शांति की ओर –सं0–डॉ0 रंगनाथ प्रसाद, पृष्ठ–18
3. भारत और भूमंडलीकरण– अभय कुमार दुबे, पृ०– 27
4. संडे टाईम्स ऑफ इंडिया, नोना वालिया (संपादक), 6 मई– 2007, पृ०– 7
5. गाँधी का सामाजिक चिन्तन, सं0–डॉ0 एम के मिश्रा डॉ0 कमल दाधीच, प्रथम संस्करण–2011, पृ0–57
6. भारतीय राजनीति विचारक–ओम प्रकाश गाबा, मयूर पेपरबैक्स, नोएडा, 2009
7. वैश्वीकरण मीडिया और समाज लेखक–रामगोपाल सिंह, नेशनल पब्लिशिंग हाउस जयपुर

8. बाजारवाद में हिंदी लेखक–डॉ0 प्रभाकर श्रोत्रिय पब्लिशर–नेशनल पब्लिशिंग हाउस संस्करण–2009
9. भूमण्डलीकरण : विचार, नीतियाँ और विकल्प लेखक –कमल नयन काबरा प्रकाशक–4268–B/3, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, 2018